Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
p-ISSN : 2395-7069 (Impact Factor : 2.0546) Volume 03, No. 02, April - June, 2017, pp. 322-324

राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की कार्यप्रणाली का विवेचन

डॉ. देवकृष्ण मण्डीवाल*

भारतवर्ष की कृषि व्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था में विशिष्ट स्थान रहा है। सही मायने में कृषि एवं पशुपालन इस अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ रहे हैं। कृषि लगभग 60 प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रूप से आजीविक प्रदान कर रही है, राष्ट्रीय आय में इसका लगभग 17 प्रतिशत योगदान तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवा रही है। पशुपालन से हमें शुद्ध दूध मिलता है जिससे दही, मक्खन, घी, छाछ, पनीर आदि उत्पाद उपलब्ध होते हैं। पशुओं को परिवहन एवं खेती के काम में भी लिया जाता है साथ ही इनके दांत, हड्डियाँ एवं चमड़ा भी अत्यधिक उपयोगी होता है। पशुपालकों को उनके दूध का उचित मूल्य दिलवाने के लिए इस देश में श्वेत क्रांति का शुभारम्भ हुआ। सर्वप्रथम गुजरात राज्य में डॉ. वर्गिज कूरियन ने आनन्द डेयरी की स्थापना की जो न कवल भारत में बल्कि विश्व में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के रूप में प्रसिद्ध है। आनन्द डेयरी पद्धति के आधार पर इस देश के विभिन्न राज्यों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया।

राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था में भी कृषि एवं पशुपालन का विशिष्ट स्थान है। यहां पर विभिन्न किस्म के लगभग 6 करोड़ पशु है। यहाँ पर गाय एवं भैस का दूध अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार पशुधन में राज्य की विशेष पहचान है। राजस्थान राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारिता के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। सर्वप्रथम जयपुर शहर के उपभोक्ताओं हेतु दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने जयपुर दुग्ध वितरण योजना के नाम से 1957 में एक विभाग आरम्भ किया। सन् 1970 के दशक के आरम्भ में राज्य सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में दुग्ध सहकारिता के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की और सन् 1972–73 में राज्य में डेयरी विकास विभाग के अन्तर्गत जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों की स्थापना की गई। वर्तमान अध्ययन राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी पर आयोजित किया गया हे। इस अध्ययन में दुग्ध उत्पादकों द्वारा दूध का संकलन, पंजीकृत समितियों का विवरण, दुग्ध भुगतान एवं प्रति किग्रा दूध की लागत आदि विवेचन किया गया है। इस आलेख का मुख्य उद्देश्य राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की कार्यप्रणाली का विवेचरण करना है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही समंको का प्रयोग किया गया है।

वर्ष 1975 में विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई, जिसके तहत 6 पूर्वी जिलों में डेयरी विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया। वर्ष 1977–78 में सहकारिता अधिनियम 1965 के अन्तर्गत राज्य में राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना की गई। राजस्थान डेयरी विकास निगम की समस्त गतिविधियों को राजस्थान सहकारी डेयरी संघ में स्थानान्तरित कर दिया गया। राज्य में डेयरी विकास गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु एनडीडीबी एवं राज्य सरकार के मध्य एक नोडल ऐजेन्सी के रूप में राजस्थान सहकारी डेयरी संघ ने अपना कार्य प्रारम्भ किया।

राजस्थान राज्य में सहकारी डेयरी का विकास एक सुस्पष्ट कार्ययोजना के अन्तर्गत संचालित किया जाता है। राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादकों/पशुपालकों द्वारा गठित एवं संचालित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ कार्यरत है। ये समितियाँ जिला स्तर पर जिला दुग्ध संघो से सम्बद्ध हैं। इस प्रकार राज्य में 21 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ स्थापित हैं, जो राज्य स्तर पर शीर्षस्थ संस्था राजस्थान सहकारी

* प्राचार्य, प्रभा देवी मेमोरियल महाविद्यालय, काबरी डूंगरी, आमेर, जयपुर, राजस्थान।